

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-के0अ0) अनुभाग-7  
संख्या: 14 /XXVII(7)पै0/2008  
देहरादून, दिनांक: 21 मार्च, 2008

कार्यालय झाप

विषय:- राज्य सरकार के सिविल/परिवारिक पेंशनरों आदि को  
महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधीनस्थताहारी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निर्देश  
हूआ है कि कार्यालय झाप संख्या-280/XXVII(7)पै0/2007,  
दिनांक: 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा महंगाई राहत की एक किश्त 01  
जुलाई 2007 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में श्री राज्यपाल द्वारा  
राज्य सरकार के सम्बन्ध सिविल पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के  
लिये लाभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त  
कार्यालय झाप दिनांक: 01 अक्टूबर 2007 में जल्लिखित दरों का  
अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2008 से महंगाई राहत की एक  
और किश्त 06 प्रतिशत (छ प्रतिशत) की दिने जाने की सहज  
स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार दिनांक: 01 जनवरी, 2008  
से राहत की दर 41 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई है।

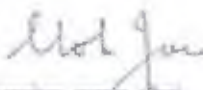
2- महंगाई राहत की ऐसी घनराशि जो एक रुपये से गुणांक में  
आगणित होगी, उसे अगले रुपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा  
आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निजामी तथा सार्वजनिक  
उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में  
सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित  
होगा।

4- यह आदेश शिक्षा/प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य  
निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे शैक्षिक एवं  
शिक्षणोत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान  
पेंशन/परिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5- शासन के कार्यालय झाप संख्या-ए- 1-252/दस/10(3)-81,  
दिनांक: 27 अप्रैल, 1982 में निम्न आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त  
राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्रधिकार पत्र की  
आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत  
का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो  
इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत लागू रहेंगे।

  
(अलोक कुमार जैन)  
मुख्य सचिव

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R.-P.C.) Section -7  
NO- 14 /XXVII(7)P/2008  
Dahradun : Dated : 21 March , 2008

Office Memorandum

Subject : Grant of Dearness Relief to state  
Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office  
memo No- 280/XXVII(7)P/2007, dated: 01October,  
2007 on the subject mentioned above sanctioning an  
instalment of Dearness Relief with effect from 01 July,  
2007 and to say that the Governor is pleased to revise  
the rates of dearness relief admissible to all civil/family  
pensioners of this Government to compensate them for  
the rise in the cost of living beyond average consumer  
price index at the rate of 6% (Six Percent) with effect  
from 01 July, 2007 in supersession of the rates  
mentioned in the O.M. dated: 01October, 2007 referred  
to above accordingly the rate of dearness of  
pension/family pension w.e.f 01-01-2008 has been  
rised to 47%.


2- Payment of dearness relief involving a fraction of a  
rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of  
High Court, Chairman and Members of Uttarakhand  
Public Service Commission, employees of local bodies  
and Public undertaking/corporation etc. In respect of  
such categories separate orders will be issued by the  
respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching  
and non-teaching pensioners of educational/ Technical  
Institutions aided by state Government whose  
Pension/Family pension is at par with the pensioners of  
the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-  
81, dated: April 27, 1982 the Accountant General  
Authority is not necessary for payment of relief of  
pension and as such the payment of dearness relief as  
admissible under this O.M. shall be made by the  
paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding dearness  
relief laid down in earlier Government orders shall  
remain as such.

  
(Alok Kumar Jain)  
Principal Secretary

संख्या: 140/XXVII(7)पै/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 3- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड।
- 5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, औबरपु मकान, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।

आज्ञा से  
(टी० एन० सिंह)  
अपर सचिव

No.140/XXVII(7)P/2008, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Principal Secretaries/Secretaries.
- 2- All Head of Department/Offices, Uttarakhand.
- 3- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Division.
- 4- Director, Treasury and Finance services, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Uttarakhand, Oberpy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- All Treasury Officers, Uttarakhand.
- 7- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.
- 8- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,  
(T.N. Singh)  
Addl. Secretary